



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 241 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 30/07/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पश्चिमी वृत्त,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:-

जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/Min/154581/2022 में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली की पत्र संख्या-8-61/1999-FC (Pt,VII) दिनांक-13 मई 2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी (वन निगम) द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अपने पत्र 297/वन स्वीकृति/दिनांक-30.06.2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया था। प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की संकलित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 384.69 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण एवं KML/Shape File सी.डी में संलग्न हैं तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-अ)
<b>i. Analysis of the proposal using Decision Support System revealed the following:</b>	
a. As per DSS analysis, out of total area of 397 ha (software estimated), 52 ha falls under MDF, 15 ha open forest, 139 ha under water and remaining 191 ha as non-wooded forest land. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.01 with no project affected trees. Discrepancy in the area may also be commented upon by the State. State also needs to justify the inclusion of 139 ha reportedly under water for proposed mining.	उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 384.69 हैक्टे0 लिया गया है। जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था। जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है, जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है।



<p>b. Tanakpur dam, NHPC Ltd. power station and a road is visible inside the area proposed for mining. Some non-forestry works is visible near the dam site which can be verified through the Google Imagery available from year 2019 onwards. State Government may comments on the same via-a-vis violation of Forest (Conservation) Act, 1980.</p>	<p>टनकपुर बैराज से अपस्ट्रीम में जलाशय क्षेत्र आर0डी0 2200 मी0 तक है तथा टनकपुर बैराज से डाउनस्ट्रीम में निर्मित 335 मीटर तक है, जो खनन हेतु प्रतिबन्धित है साथ ही एन0एच0पी0सी0 द्वारा पावर स्टेशन तक नहर के किनारे निर्मित की गई सड़क का प्रयोग एन0एच0पी0सी0 द्वारा किया जाता है साथ ही आवंटित बॉध क्षेत्र में एन0एच0पी0सी0 द्वारा समय-समय पर बॉध की मरम्मत कार्य किया जाता है। (छायाप्रति संलग्न-1)</p>
<p>c. KML file of the safety zone has not been submitted/uploaded online.</p>	<p>(छायाप्रति संलग्नक-2 )</p>
<p>d. As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga_Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी की पत्र संख्या 173/ 12-1/दिनांक 20.07.2022 के द्वारा दुधवा-लगगा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरीडोर के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लिखा गया है। पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-ब)</p>
<p><b>ii. Examination of the Mining scheme revealed the following:</b></p>	
<p>e. Mining Plan/Scheme mention that time extension of lease has been granted for a period of another 10 years vide Government letter dated 26.06.2020. It needs to be clarified by the State whether the extension is considered over 55.03 ha or entire area of 384.69 ha approved under the FC Act, 1980.</p>	<p>आगामी 10 वर्षों के शारदा नदी के खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 384.69 हैक्टे0 है। जिसमें अपस्ट्रीम 101.00 हैक्टे0 तथा डाउनस्ट्रीम 283.69 हैक्टे0 है। जिसमें नदी के दोनों किनारों की ओर 25-25% छोड़ा जाता है। एवं नदी के टापू के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान माईनिंग प्लान में डाउनस्ट्रीम 55.3 हैक्टे0 क्षेत्र दर्शित है।</p>
<p>f. Comments of State on validity of Mining Plan / Scheme after 12.02.2023 i.e. whether any revised Mining Plan and renewal of lease is under consideration or granted by the State for further period after the expiry of the lease. In case the certain forest areas are not to be considered mining, such areas should be surrendered back to Forest Department.</p>	<p>इस प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है तथा भविष्य हेतु 05 व र्तीय माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।</p>
<p>e. Lease has been considered for extension for a period of 10 years while the Scheme of Mining has been submitted only up-to 27.12.2020. The discrepancy needs to be rectified by the State.</p>	<p>इस प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 11.02.2023 तक है तथा आगामी वर्षों हेतु माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।</p>
<p>f. Land use / Component wise breakup of the area proposed for diversion i.e. area under mining, infrastructure, approach road, storage of top soils, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining Scheme. The same needs to be furnished by the State.</p>	<p>खनन क्षेत्र में दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग को छोड़कर शेष भाग में खनन कार्य किया जाता है इस कारण केवल 192.345 है0 क्षेत्र में ही खनन किया जाता है खनन योग्य क्षेत्र में कोई भी infrastructure नहीं है तथा Approach road को माईनिंग प्लान की प्लेट संख्या 06 में दिखाया गया है।</p>



g. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the State providing the full detail of the land use, mining area, its reclamation, etc.	02 वर्ष की खनन योजना, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा 05 साल हेतु खनन योजना प्रस्ताव प्रस्तावित है।
h. Status of District Survey Report, if any, prepared by the State Government in Champawat District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining - 2019 issued by the Ministry vis-à-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	चम्पावत जिले की जिला सर्वे रिपोर्ट संलग्नक की जा रही हैं। (छायाप्रति संलग्नक -5)
i. The State Government may also submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के Sustainable Sand Mining Guidelin में 2016 अनुरूप है, उनके द्वारा दिया गया पत्र संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक -6)
j. Details of estimation of cost benefit ratio has not been provided / uploaded online. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure -III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.	लाभ तालिका संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक -7)
k. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर0बी0एम0 की बिक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभाग को दिया जाता है विगत वर्षों का विवरण संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक -8)
l. Details of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.	एस0पी0वी0 की धनराशि का विगत वर्षों का विवरण संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक -8)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।  
(दो प्रतियां)

भवदीय,  
  
(बाबू लाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी





कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर  
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी



टनकपुर (शारदा) वन परिसर, कार्ड नम्बर- 8, जनपद- चम्पारन, E-mail- roshardarange@gmail.Com

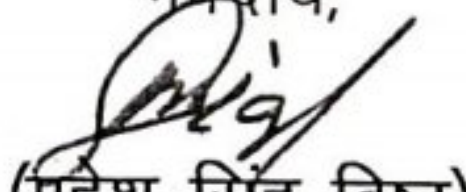
पत्रांक :- 133 / 7-1, टनकपुर, दिनांक :- 26 / 07 / 2022  
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,  
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय :- हस्तान्तरित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक से सादर अवगत कराना है, कि शारदा वन क्षेत्र के अन्तर्गत F.No- 8-61/1999 FC (Pt-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान के सापेक्ष के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- यथोपरि।


भवदीय,  
  
(महेश सिंह बिष्ट)  
वन क्षेत्राधिकारी,  
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर




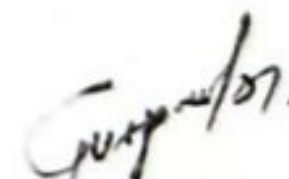
वर्ष	प्रभाग का नाम	परियोजना का नाम जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित किया गया है	हस्तान्तरित वन भूमि	हस्तान्तरित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण			सफलता प्रतिशत	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति	
				रेंज का नाम	स्थल का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल (है० में)				रोपित पौधों की संख्या
2015	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	F.No- 8-61/1999 FC (PI-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान। (384.69 हैक्टेयर)	-	शारदा	शारदा द्वितीय वीट शारदा टापू संख्या 35 व 38 के मध्ये	25	12500	70%	2014000.00	-
2016			-	शारदा	शारदा टापू संख्या 42	16	16000	75%	889688.00	-
2016			-	शारदा	शारदा टापू संख्या 36	28	28000	90%	1385467.00	-
2016			-	शारदा	शारदा टापू संख्या 43 व 44 के मध्य	16	16000	80%	1030047.00	-
2016			-	शारदा	शारदा टापू संख्या 37 में	63	63000	78%	3218523.00	-
2020			-	शारदा	शारदा टापू संख्या- 36	20	20000	85%	1913554.00	-
2020			-	शारदा	शारदा टापू संख्या- 34 व 35 मध्ये	20	20000	80%	2007748.00	-
2021			-	शारदा	शारदा टापू संख्या- 35 व 36 मध्ये	20	22000	90%	2000351.00	-
2021			-	शारदा	शारदा टापू संख्या- 37	20	22000	91%	1617520.00	-
2022			-	शारदा	शारदा टापू सं०- 37 भाग-01	21	23100	100%	1965091.00	वर्तमान में अग्रिम मृदा कार्य की धनराशि व्यय की गयी है, तथा वनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा वनीकरण की धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है।
2022			-	शारदा	शारदा टापू सं०- 42	20	22000	100%	2020725.00	



2022	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	F.No- 8-61/1999 FC (Pt-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान। (384.69 हैक्टेयर)	-	शारदा	शारदा टापू सं०- 36 भाग-01	15	16500	100%	2004463.00	वर्तमान में अग्रिम मृदा कार्य की धनराशि व्यय की गयी है। वनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा वनीकरण की धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है।
2022			-	शारदा	शारदा टापू सं०- 41	14	15400	100%	1463937.00	
2022			-	शारदा	शारदा टापू सं०- 35 एवं 37 मध्ये भाग-01	22	24200	100%	2095439.00	
2022			-	शारदा	शारदा टापू सं०- 35 एवं 37 मध्ये भाग-02	22	24200	100%	2140311.00	
2022			-	शारदा	शारदा टापू सं०- 14	7	7700	100%	1141345.00	
2022			-	शारदा	शारदा टापू सं०- 36 भाग- 02	21	23100	100%	2139503.00	
2022			-	शारदा	शारदा टापू सं०- 13	15	16500	100%	903688.00	
						सम्पूर्ण योग-	385	392200	-	

  
(महेश सिंह बिष्ट)  
वन क्षेत्राधिकारी,  
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर।

  
(महेश सिंह अधिकारी)  
वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी,  
शारदा टापू अनुभाग।

  
(पुष्पेन्द्र सिंह राणा)  
वन बीट अधिकारी,  
शारदा टापू द्वितीय बीट।





उत्तराखण्ड शासन

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 173 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक

20.07.2022

सेवा में,

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,  
राजपुर रोड,  
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय:-

जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत स्थित शारदा नदी में 384.69 है० क्षेत्र के चुगान कार्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ MIN/154581/2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा 384.69 है० क्षेत्र में उप-चुगान कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अवधि वर्ष फरवरी 23 में समाप्त हो रही है। पुनः आगामी दस वर्ष का प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था, जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या-8-61/1999-एफ.सी. (पार्ट-II) दिनांक-13 मई 2022 द्वारा प्रकरण में आपत्ति उठायी गयी है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में यह आपत्ति उठायी गयी है कि उक्त क्षेत्र दुधवा-लग्गा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर की सीमा से लगभग 3 कि.मी. (1.6 कि.मी. हवाई दूरी) की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित प्रस्ताव पर मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया प्राप्त की जाय। जिसे मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्तुत किया जाएगा।

महोदय यद्यपि प्रश्नगत क्षेत्र दुधवा-लग्गा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर से 3.00 किमी. की सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं एवं पूर्व में भी 10 वर्षों के लिए उप चुगान की अनुमति प्रदान की गयी थी। यह भी अवगत कराना है कि उप चुगान से वन्य जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अतः अनुरोध है कि प्रकरण में उठायी गयी आपत्ति पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी